राजमार्गों के विकास के लिए समिति का गठित किया जाना ।

3780. **श्री राम सिंह रठवा** क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजमार्गों के विकास के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें दी हैं; और

(ग) ये सिफारिशें किस सीमा तक कार्यान्वित की गई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि का स्वीकृत किया जाना और जारी किया जाना

3781. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सड़कों के निर्माण के लिए राज्यवार कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी राशि जारी की गई, और

(ख) किन कारणों से स्वीकृत धन-राशि की अपेक्षा कम राशि जारी की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय 1991–92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जारी किए गए आवंटन से है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिये)**

(ख) संभवतः माननीय सदस्य, राज्यों द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में कम राशि जारी करने के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए किए गए कम आवंटन के कारण विभिन्न राज्य सरकारों की मांगों को पूर्णतः पूरा करना संभव नहीं था ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रु०)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2455.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.00
3.	असम	1225.00
4.	बिहार	1142.00
5.	चण्डीगढ़	28.00
6	दिल्ली	550.00
7.	गोवा	930 00
8.	गुजरात	4770.00
9.	हरियाणा	1060.00

10. हिमाचल प्रदेश	1140.00
11. जम्मू और कश्मीर	50.00
12. कर्नाटक	1775.0
13. केरल	1120.00
14. मध्य प्रदेश	1850.00
15. महाराष्ट्र	3358.00
16. मणिपुर	250.00
17. मेघालय	450.00
18. नागालैण्ड	48.00
19. उड़ीसा	1384.00
20. पाण्डिचेरी	120.00
21. पंजाब	2850.00
22. राजस्थान	1800.00
23. तमिलनाडु	1422.00
24. उत्तर प्रदेश	6025.00
25. पश्चिम बंगाल	1634.00
योग :	37484.00

राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत परिवहन सुविधायें

3782. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1990-91 के प्रस्ताव के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत परिवहन सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं की गई हैं,

(ख) इस सम्बन्ध में कौन-कौन से काम पूरे कर लिये गये हैं और कौन-कौन से कार्य पूरे किये जाने शेष हैं, और

(ग) राष्ट्रीय जलमार्गों को कब तक जनता के लिए खोल दिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 1990-91 में राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली के इलाहाबाद-हल्दिया खंड) के हल्दिया-बलिया खण्ड में नौचालन के लिए 1.5 मीटर गहरा और 45 मीटर चौड़ा नेवीगेशन चैनल उपलब्ध करवाया गया था और भागलपुर, मुंगेर तथा पटना में टर्मिनल सुविधाएं कायम रखी गई ताकि कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग की जा सके। ब्रह्मपुत्र के धुबरी-यामरी खण्ड में 2.0 मीटर गहरा और 45 मीटर चौड़ा नेवीगेशन चैनल उपलब्ध करवाया गया। दोनों जलमार्गों में नेवीगेशन चैनलों को दिन के समय नौचालन के लिए चिह्नित किया गया।

पटना में 4.90 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण की योजना को सितम्बर, 1991 में स्वीकृति दी गई थी। इस योजना को 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है।

(ग) दोनों जलमार्गों में पहले ही अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रचालन किए जा रहे हैं।